दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN16931 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, रविवार 2 दिसम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-65

महत्वपूर्ण एवं खास

पूर्व प्रेसीडेंट जॉर्ज बुश का 94 साल की उम्र में निधन

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज एच डब्ल्यू बुश का निधन हो गया है। वह 94 वर्ष के थे और काफी लंबे समय से बीमार थे। उनके प्रवक्ता जिम मैकग्रैथ के मुताबिक बुश परिवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बुश का निधन अमेरिकी समयानुसार शुक्रवार शाम को हुआ। उनकी पत्नी बारबरा की मृत्यु इस साल 17 अप्रैल को हुई थी। उनका 73 साल का विवाह यूएस इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के मुकाबले लंबा था। पत्नी की मौत के कुछ हफ्तों बाद ही बुश की भी तबियत बिगड़ गई थी। इन्फेक्शन के चलते बुश सीनियर को इस साल अप्रैल से ही आईसीयू में रखा गया था।

निजी विमान हादसे में कई लोगों ने गंवाई जान

शिकागो (आरएनएस)। अमेरिका के इंडियाना राज्य में शुक्रवार को शिकागो जाने वाले एक छोटा जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई लोगों की मौतें हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सेस्ना सिटेशन सी 525 नाम का निजी विमान का इंडियाना के क्लार्क क्षेत्रीय हवाई अड्डे से शिकागो मिडवे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने के बाद लगभग पूर्वाह्न 11:30 (स्थानीय समय) बजे हवाई यातायात रडार से संपर्क टूट गया।

भूकंप के बाद अलास्का में आपातकाल

वाशिंगटन (आरएनएस)। अमेरिका के अलास्का प्रांत में कल भीषण भूकंप आने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकाल की घोषणा की है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर सात आंकी गई है और इससे बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद 40 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। व्हाइट हाऊस के प्रवक्ता के अनुसार आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अलास्का प्रांत में आपातकाल लागू हो गया है और संघीय एजेंसियां राज्य में मदद पहुंचा सकती हैं।आपातकाल की इस घोषणा के बाद गृह विभाग और संघीय आपातकाल प्रबंधन एजेंसी आपदा प्रबंधन प्रयासों में समन्वय स्थापित करेंगी तथा इन कार्यों के लिए आर्थिक सहायता भी देंगी। अभी तक भूकंप के कारण किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

सीनियर सिटीजन पेंशन के लिए दूसरे स्थानों से कोष नहीं ले सकते

नयी दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के रास्ते में धन संबंधी अड़चनें आती हैं क्योंकि सरकार अन्य स्थानों से धन ''नहीं ले सकती।'' सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार की दलीलों का जवाब देते हुए यह बात न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ से कही। उन्होंने ने एक याचिका दायर करके केन्द्र को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में तय 200 और 500 रुपये की मासिक पेंशन बढाने का निर्देश देने की मांग की थी। उनकी याचिका पर केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने कहा कि पेंशन की तुलना न्यूनतम वेतन से नहीं की जा सकती। हम अन्य जगहों से धन नहीं ले सकते।

अब ड्रोन से पहुंचाए जाएंगे अंग

नई दिल्ली (आरएनएस)। अंग परिवहन के लिए ट्रैफिक की समस्या से निपटते हुए ड्रोन की मदद ली जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री ने कहा कि अथॉरिटी हॉस्पिटलों में ड्रोनपोर्ट्स बनाने की तैयारी कर रही है। बड़े ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन आज 1 दिसंबर से शुरू होगा। इसके लिए एक महीने बाद लाइसेंस इशू करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हम अपनी ड्रोन पॉलिसी 2.0 पर काम कर रहे हैं। जिसके तहत ड्रोन को नजर से दूर रखकर उड़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया बड़े हॉस्पिटल के बीच एयर कॉरिडोर बनाने पर भी विचार चल रहा है।

अब पब्लिक फीडबैक के आधार पर तय होगी अधिकारियों की तरक्की

नई दिल्ली (आरएनएस)। आगामी सत्र से सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन में सबसे अहम भूमिका पब्लिक फीडबैक की रहेगी। इसके अंतर्गत जिस अधिकारी और कर्मचारियों की ग्रेडिंग बेहतर होगी, उन्हें बेहतर प्रमोशन मिल सकेगा। किसी प्रॉडक्ट की तरह इन कर्मचारियों की भी ग्रेडिंग करने का पूरा सिस्टम बनाया गया है। इस दिशा में पिछले दिनों सरकार को एक प्रस्ताव मिला था।

मिली जानकारी के मुताबिक पीएमओ के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग ने इस प्रस्ताव को मान लिया है और 1 अप्रैल 2019 से नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी कामकाज के दौरान आम लोगों

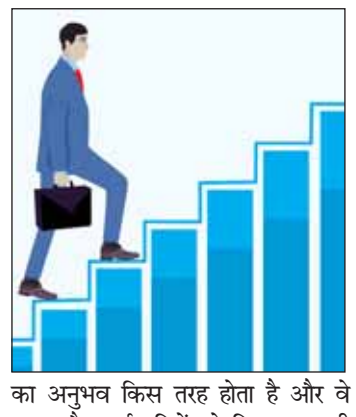

का अनुभव किस तरह होता है और वे बाबू और कर्मचारियों को किस तरह की ग्रेडिंग देंगे, इसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। आम लोगों की ओर से मिली ग्रेडिंग इन अधिकारियों के प्रमोशन से लेकर वेतन वृद्धि तक तय करेगी। पीएमओ के निर्देश पर इसका फॉरमैट तैयार किया गया।

सातवें वेतन आयोग ने दिया था सुझाव

नए परिपत्र में अधिकारी के कामकाज को ग्रेड और अंक देने की व्यवस्था है। इसे उस अधिकारी और कर्मचारी के रेकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब कि अब केंद्र सरकार के दफ्तरों में फाइव स्टार या वन स्टार अधिकारी या कर्मचारी के बारे में लोग पहले ही जान सकेंगे। दरअसल, सातवें वेतन आयोग में इनके कामकाज की समीक्षा को और बेहतर करने के कई सुझाव दिए गए थे। जिन मंत्रालयों और विभागों का अधिकतर वास्ता सीधे आम लोगों से पड़ता है, वहां अब प्रमोशन और बेहतर अप्रेजल के लिए 80 फीसदी वजन पब्लिक फीडबैक को दिया जाएगा।

सीएम से असहमत हों सिद्धू तो कैबिनेट से दें इस्तीफा

पंजाब सरकार के मंत्री बाजवा ने कहा

चंडीगढ़ (आरएनएस)। गुरुनानक देव की निर्वाणस्थली करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम में पाकिस्तान जाने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के सामने एक और मुश्किल आन पड़ी है। सिद्धू द्वारा खुले तौर पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से असहमति जताने के बाद अब पंजाब में उनके साथ कैबिनेट मंत्री ने उनका इस्तीफा मांगा है।

पंजाब सरकार में मंत्री त्रिपत बाजवा ने कहा है कि अगर सिद्धू अमरिंदर सिंह को अपना नेता नहीं मानते हैं, तो उन्हें पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्ञात

हो कि इससे पहले शुक्रवार को तेलंगाना के चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे सिद्धू ने यहां मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना कैप्टन बताया था।

हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमिटी की बैठक के दौरान सिद्धू ने कहा, मुझे राहुल गांधी ने पाकिस्तान जाने को कहा था। सीएम सिंह ने मुझे रोका था, लेकिन मेरे कैप्टन तो राहुल गांधी हैं। कैप्टन (अमरिंदर सिंह) के भी कैप्टन राहुल गांधी ही हैं। पाकिस्तान से लौटकर आने पर शशि थरूर, हरीश रावत, रणदीप सुरजेवाला जैसे शीर्ष नेताओं ने मेरी पीठ भी थपथपाई थी।

पाक के दौरे पर गए थे सिद्धू

बता दें कि कुछ दिन पहले ही पाक में करतारपुर में कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसके शिलान्यास के लिए सिद्धू को भी न्योता दिया गया था और वह वहां गए भी थे। सिद्धू ने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान जाने पर जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग यूटर्न ले रहे हैं। यही नहीं मैंने पाकिस्तान के नेताओं से वादा किया था कि दोबारा आऊंगा और मैंने अपना वादा निभाया।

3000 करोड़ के रक्षा सौदों को मिली मंजूरी, निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता

नई दिल्ली। शनिवार को रक्षा अधिग्रहण समिति (डीएसी) ने करीब 3000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है. इस खरीद के तहत भारतीय नौसेना के दो जहाजों के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें, और भारतीय थल सेना के मुख्य युद्धक टैंक 'अर्जुन' के लिए आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल (एआरवी, बख्तरबंद वाहन) खरीदे जाएंगे. डीएसी की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इस साल अक्टूबर में चार पी 1135.6 फॉलो-ऑन जहाजों की खरीद के लिए सीसीए के फैसले के रूप में, डीएसी ने भारतीय नौसेना के दो जहाजों के लिए स्वदेशी ब्राह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए मंजूरी दी. स्वदेशी डिजाइन के ब्राह्मोस मिसाइल ने परीक्षण के बाद यह सिद्ध कर दिया था कि यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है.

न्यूजीलैंड में 51 पायलट व्हेलों की मौत

वेलिंगटन (आरएनएस)। न्यूजीलैंड में एक सप्ताह से भी कम समय में 51 पायलट व्हेलों की एक ही जगह पर फंसने के कारण मौत हो गयी। इससे पहले देश में एक अन्य जगह 145 पायलट व्हेलों की मौत हुई थी। पायलट व्हेल, व्हेल की एक प्रजाति है। इन्हें ब्लैकफिश के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड के संरक्षण विभाग ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुदूरवर्ती चाथम द्वीप पर 90 पायलट व्हेल तट पर देखी गयी थीं।

मणिपुर में एफआईआर के खिलाफ 700 सैनिकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में एनकाउंटर को अंजाम देने वाले सैन्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका 700 सैन्य कर्मियों की तरफ से दाखिल की गई थी। इन क्षेत्रों में सेना को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15-20 साल पुराने कई केसों में आर्मी ने जांच भी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसों में सीबीआई जांच

का आदेश दिया है।

कई मामलों में नहीं हुई जांच

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर और यूयू ललित ने कहा, अशांत क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को हम समझते हैं। इसलिए हम लोग कई बार अटॉर्नी जनरल से 15-20 साल में हुए फर्जी एनकाउंटर मामलों की जांच के लिए कह रहे हैं। जब हमने पाया कि इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है तो, हमने कुछ मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। खास तौर पर उन मामलों में जिनमें पहली नजर में ही हाई कोर्ट, न्यायिक आयोग और जस्टिस संतोष हेगड़े कमिशन या एनएचआरसी में फर्जी एनकाउंटर का अंदेशा होता है।

राजधानी में सुबह धुंध छाई, वायु गुणवत्ता बेहद खराब

नई दिल्ली (आरएनएस)। राजधानी में शनिवार को सुबह धुंध छाये रहने के कारण यहां का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब पर पहुंच गया। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली ने यह जानकारी दी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारी का कहना है कि दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

रामायण के अनुसार हनुमान आर्य थे

अब केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह का दावा

बागपत (आरएनएस)। इन दिनों बजरंगबली वीर हनुमान की जाति और पहचान बताने को लेकर राजनेताओं में होड़ सी लगी हुई है। अब इस कतार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय के बाद अब केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह भी शामिल हो गए हैं। बागपत से भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने हनुमान की पहचान को लेकर नई बात कही है।

उन्होंने कहा कि भगवान राम

और हनुमान जी के युग में, यहां कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। कोई दलित, वंचित और शोषित नहीं था। वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस का हवाला देते हुए उन्होंने अपने कथन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उस समय केवल आर्य थे और हनुमान जी उस आर्य जाति के महापुरुष थे।

ज्ञात हो कि नंद कुमार साय ने कहा था, आदिवासियों में हनुमान गोत्र होता है। ठीक उसी तरह रीछ और गिद्ध गोत्र भी होता है। यहां तक कि आदिवासी तिग्गा गोत्र भी लिखते हैं। टिग्गा का मतलब होता है वानर या बंदर। यहां कई आदिवासी समुदाय हैं जिनके अलग-अलग गोत्र होते हैं। जब भगवान राम लंका पर हमला करने गए थे तब उनकी वानरों के सेना में दो वानर गरुण और रीछ भी थे। इनमें हनुमान भी शामिल थे।

तीन साल की बेटी के साथ रेप करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरियाणा। 28-29 नवंबर की मध्यरात्रि रात को गुरुग्राम में अपनी 3 साल की बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है । प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शीत सत्र से पहले एकजुट विपक्ष किसान मुद्दे को बनाएगा एजेंडा

किसान रैली में भी विपक्षी दिग्गजों ने तेवर दिखा कर दिए साफ संकेत

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और भाजपा के राम मंदिर मुद्दे का जवाब विपक्ष किसान से देगा। शुक्रवार को सरकार और भाजपा के प्रतिनिधिनिधियों की अनुपस्थिति के बीच किसानों की रैली में विपक्षी दलों के जमघट ने सियासी बानगी पेश कर दी है। रैली से जहां सरकार और भाजपा ने दूरी बनाई, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, फ ारुख अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी समेत कई विपक्षी दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध कर अपनी भविष्य की रणनीति का इजहार कर दिया है।

विपक्ष खासातौर पर राम मंदिर की काट के लिए किसानों के मुद्दे पर पर

संसद में मोदी सरकार को घेरने की योजना बना रही है। पार्टी की इस मुद्दे पर राकांपा, नेशनल कांफ्रेंस, इस रैली का पत्र के माध्यम से समर्थन करने वाले पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी से बात हुई है। उ मीद है कि सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक में किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का सर्वस्वीकार्य रोडमैप तैयार हो जाए। वैसे भी सरकार और भाजपा के राम मंदिर कार्ड से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल असहज हैं। खासतौर पर इस कार्ड से नरम हिंदुत्व का चोला पहने कांग्रेस ज्यादा ही असहज है।

वैसे भी किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के पास सरकार को घेरने का बड़ा मौका है। वह इसलिए कि किसान वही मांग कर रहे है जिसकी घोषणा भाजपा ने बीते चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने चुनाव घोषण पत्र में की थी। तब भाजपा ने स्वामीनाथ कमीशन की सिफारिशें लागू करने और फसल की लागत की तुलना में डेढ़ गुणा कीमत देने का वादा किया था। जहां तक कर्ज माफ करने का सवाल है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगातार इस आशय का आश्वासन दे रहे हैं।

किसान के मुद्दे पर नाराजगी की बानगी सरकार को गुजरात विधानसभा चुनाव केदौरान ही दिख गई थी। हालांकि रणनीतिगत उपाय ढूंढने में हुई लापरवाही के कारण किसान का मुद्दा मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में छाया रहा तो राजस्थान सहित शेष दो राज्यों में भी यह अहम मुद है। अब लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा अपने चरम पर जाता दिख रहा है। सरकार की मुश्किल यह है कि इस बार के किसान आंदोलन को डाक्टरों, वकीलों, पूर्व सैनिकों, पेशेवरों, मध्यवर्ग के युवाओं का खासा समर्थन हासिल हो रहा है।

मंदिर पर समर्थन के लिए विहिप ने मांगा सोनिया-राहुल से समय

नई दिल्ली (आरएनएस)। राम मंदिर मुद्दे पर आगामी 11 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को गर्माने के लिए संघ ने कमर कस ली है। इस मोर्चे पर संघ ने विहिप को सियासी दलों को साधने की जि मेदारी दी है तो रथ यात्रा के माध्यम से 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी स्वदेशी जागरण मंच को दी है। इस क्रम में विहिप की अमेठी और रायबरेली इकाई राम मंदिर पर समर्थन केलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगेगा। जबकि मंच शनिवार से 11 दिसंबर तक संकल्प रथ यात्रा निकालेगा।

विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार केमुताबिक विहिप जल्द ही राम मंदिर निर्माण के लिए कानून की मांग करने संबंधी भाजपा सांसद राकेश सिन्हा की ओर से पेश किए जाने वाले निजी बिल पर सभी दलों के सांसदों का समर्थन मांगेगी। इस क्रम में संगठन के अमेठी और रायबरेली इकाई अपने स्थानीय सांसदों राहुल और सोनिया से मिलने का समय मांगेगी।